

देश को निष्पक्ष लोग चाहिए निष्पक्षता कमजोरी नहीं, लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है

देश को आज सबसे ज्यादा जरूरत नारे लगाने वालों की नहीं, निष्पक्ष सोच रखने वाले लोगों की है। ऐसे लोगों की, जो सत्ता को सत्ता के चश्मे से नहीं, जनता के अधिकारों के चश्मे से देखें; विपक्ष को दुश्मन नहीं, लोकतांत्रिक व्यवस्था का आवश्यक हिस्सा समझें; और गलत को गलत कहने का साहस रखें—चाहे गलती अपने ही खेमे की क्यों न हो।

आज हमारी सबसे बड़ी समस्या केवल भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी या प्रशासनिक अव्यवस्था नहीं है। उससे भी गंभीर संकट छे—पक्षपात की मानसिकता। हम व्यक्ति देखकर सच का अर्थ बदल देते हैं। अपना आदमी गलती करे तो मजबूरी, दूसरा करे तो अपराध! अपने पक्ष का नेता बोले तो राष्ट्रहित, विरोधी बोले तो राजनीति! यही दोहरा मापदंड लोकतंत्र की आत्मा को कमजोर करता है।

अंधसमर्थन लोकतंत्र नहीं है और अंधविरोध भी लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र में सवाल पूछना अधिकार है और जवाब देना जिम्मेदारी। जनता किसी नेता, दल या संस्था की स्थायी संपत्ति नहीं है। जनता का विश्वास काम से मिलता है और जवाबदेही से कायम रहता है।

सबसे बड़ा सवाल यह है कि निष्पक्ष लोग कहाँ हैं?

क्या हम हर मुद्दे को जाति, धर्म, क्षेत्र, पार्टी और व्यक्तिगत पसंद की तराजू पर ही तौलते रहेंगे? क्या न्याय भी अब पहचान देखकर मिलेगा? क्या कानून की गंभीरता इस बात पर निर्भर करेगी कि आरोपी कौन है? यदि ऐसा हुआ तो संविधान की किताब तो बची रहेगी, लेकिन उसके मूल्यों की आत्मा कमजोर होती जाएगी।

आज देश को ऐसे नागरिक चाहिए जो कह सकें—“मेरी पसंद अपनी जगह, लेकिन सत्य अपनी जगह।”

ऐसे पत्रकार चाहिए जो सवाल पूछें, ऐसे अधिकारी चाहिए जो नियम के अनुसार काम करें, ऐसे जनप्रतिनिधि चाहिए जो जनता के प्रति जवाबदेह रहें और ऐसे नागरिक चाहिए जो सुविधा के अनुसार नहीं, सिद्धांत के अनुसार आवाज उठाएं।

निष्पक्षता का अर्थ चुप रहना नहीं है।

निष्पक्ष व्यक्ति अन्याय के सामने खड़ा होता है, लेकिन उसका हथियार नफरत नहीं—तथ्य, संविधान और न्याय होता है। वह सरकार की अच्छी बात की सराहना भी कर सकता है और गलत निर्णय पर सवाल भी उठा सकता है। यही स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है।

AIHRA — All India Human Rights Association का मानवाधिकार दृष्टिकोण भी यही संदेश देता है कि मानव गरिमा, समानता और न्याय किसी दल, जाति या वर्ग की संपत्ति नहीं हैं। मानवाधिकार का असली अर्थ तभी जीवित रहेगा जब हम अधिकारों को चयनात्मक नहीं, सार्वभौमिक मानेंगे।

आज जरूरत है एक नए सामाजिक संकल्प की—न व्यक्ति—पूजा, न व्यक्ति—द्वेष, न अंधसमर्थन, न अंधविरोध;

सिर्फ सत्य, संविधान, मानवता और जवाबदेही। क्योंकि देश को हर बात पर तालियां बजाने वाले लोग नहीं, सही समय पर सही सवाल पूछने वाले निष्पक्ष लोग चाहिए।

और याद रखिए : जब नागरिक निष्पक्ष होना छोड़ देता है, तब सत्ता ही नहीं, पूरा समाज जवाबदेही खो देता है।

देश बचेगा तो हम बचेंगे; लोकतंत्र बचेगा तो हमारी आवाज बचेगी; और निष्पक्षता बचेगी तो न्याय बचेगा।

THE COUNTRY NEEDS IMPARTIAL PEOPLE

Impartiality is not weakness—it is the greatest strength of democracy.

The country today does not need more people who merely raise slogans. It needs people with an impartial mind—people who can look at power through the eyes of citizens' rights, who understand that opposition is not an enemy but an essential part of democracy, and who have the courage to call wrong “wrong,” even when the mistake comes from their own side.

Our biggest challenge is not limited to corruption, inflation, unemployment or administrative failures. An even deeper crisis is the culture of selective thinking and double standards. We often change the meaning of truth depending on who is involved. If our own side makes a mistake, we call it a “compulsion”; if someone else does the same thing, we call it a “crime.” If our preferred leader speaks, it is called national interest; if the opponent speaks, it is called politics.

This double standard slowly weakens the soul of democracy.

Blind support is not democracy, and blind opposition is not democracy either. In a democracy, asking questions is a right and answering them is a responsibility. The people are not the permanent property of any leader, political party or institution. Public trust is earned through performance and sustained through accountability.

The serious question is: Where are the impartial people?

Will we continue to judge every issue through the lenses of caste, religion, region, political affiliation and personal preference? Will justice also depend upon identity? Will the seriousness of an allegation change depending upon who is involved? If that happens, the Constitution may remain on paper, but the spirit behind its values will gradually become weaker.

The country needs citizens who can say:

“My preference is one thing, but the truth is another.”

We need journalists who ask difficult questions, officials who follow rules, public representatives who remain accountable to citizens, and ordinary people who speak according to principles rather than convenience.

Impartiality does not mean remaining silent.

An impartial person stands against injustice, but does not use hatred as a weapon. The weapons are facts, constitutional values,

reason and justice. Such a person can appreciate a government's good work and, at the same time, question a wrong decision.

That is the foundation of a healthy democracy.

The human-rights perspective of AIHRA — All India Human Rights Association reinforces the principle that human dignity, equality and justice cannot belong exclusively to any political party, caste or social group. Human rights remain meaningful only when we defend them universally, not selectively.

What the country needs today is a new social commitment:

Neither personality worship nor personality hatred;

neither blind support nor blind opposition;

only truth, constitutional values, humanity and accountability.

Because the country does not need people who clap at everything.

It needs impartial citizens who have the courage to ask the right questions at the right time.

Remember:

If citizens abandon impartiality,

accountability disappears—not only from power,

but from society itself.

If the country survives, we survive.

